नवभारत टाइम्स

नई दिल्ली, 8 नवम्बर 1996

बहस

अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष का दबाव

हमारा मत है कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा राजकोषीय घाटा कम करने के लिए भारत पर दिया जा रहा दबाव अनुचित और आपत्तिजनक है।

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत सरकार से कहा है कि वह अपना राजकोषीय घाटा कम करे। ऐसा मुद्रा कोष ने कोई पहली बार नहीं कहा है। भारत ने पांच छह साल पहले जब विदेशी मुद्रा संकट की घड़ी में कोष से सहायता ली थी, तो सहायता की शर्तों में राजकोषीय घाटे को कम करना भी शामिल था। भारत ने इसके लिए प्रयास भी किए। नई आर्थिक नीतियों को लागू करते समय भारत सरकार के दिमाग में दो महत्वपूर्ण बातें थीं। पहला अर्थव्यस्था को नियंत्रण की जकड़न से मुक्त करके उद्यमियों के प्रति इसे उदार बनाना तथा दूसरा, राजकोषीय घाटे को कम करके घाटे की अर्थव्यवस्था को समाप्त करना। उदारीकरण की दिशा में तो कुछ सफलता मिली है, लेकिन घाटे की अर्थव्यवस्था को समाप्त नहीं किया जा सका। यह देश के हित में ही है कि राजकोषीय घाटा समाप्त हो जाय। लेकिन इसके लिए बाहरी दबाव पड़ना अत्यंत हीं आपत्तिजनक है। इसके लिए कोई बाहरी संस्था भारत को दिशा निर्देश दे तो इससे देश की संप्रभुता पर आक्रमण होता है। घाटे को कम करने के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जो तरीका बताता है, उससे देश में एक उच्च लागत की अर्थव्यवस्था अस्तित्व में आ जाती है। भारत जैसे गरीब और घोर आर्थिक विषमता वाले देश के लिए घाटा कम करने का मुद्रा कोष द्वारा बताया गया रास्ता खतरनाक हो सकता है। इसकी एक झांकी हम पाकिस्तान में देख चुके हैं, जहां राजकोषीय घाटा समाप्त करने के लिए किए गए बजट प्रावधानों के खिलाफ पाकिस्तान की जनता सड़कों पर उतर आई। लाचार होकर बेनजीर भुट्टो को वित्त मंत्रालय छोड़ना पड़ा था। बजट से उपजे असंतोष ने भी वहां के राष्ट्रपति को बेनजीर को प्रधानमंत्री पद से बर्खास्त करने के लिए प्रेरित किया। इसलिए भारत सरकार को मुद्रा कोष के दबाव में नहीं आना चाहिए।

प्रतिसंपादकीय/ इंडियन इंस्टीच्युट ऑफ फाइनेंस के निदेशक प्रो. जे डी अग्रवाल का कहना है कि सही रणनीति अपनाकर हम राजकोषीय घाटे को इतना कम कर सकते हैं कि आइ एम एफ को भारत पर दबाव डालने की जरूरत ही न पड़े।

राजकोषीय घाटा कम करने के प्रसंग में सबसे पहले यह देखना होगा कि सम्बद्ध देश विकसित है या विकासशील। बिना इसे जाँचे हुए यह मुद्दा नहीं उठाना चाहिए। राजकोषीय घाटे को नियंत्रण में रखना या न रखना किसी देश के लिए उद्देश्य नहीं हो सकता। उद्देश्य तो उस देश का आर्थिक विकास करना है। आर्थिक विकास के लिए जरूरी है कि उस देश में निवेश हो। विकासशील देशों में निवेश की पूँजी के लिए मांग बहुत अधिक है। क्योंकि ऐसे देशों में मूल ढांचागत विकास पूरी तरह नहीं हुआ होता है। राजकोषीय घाटा नियंत्रण में रखने के लिए एक और तरीका यह भी हो सकता है कि विकास दर को स्थगित कर दिया जाए। लेकिन यह तरीका देश को पिछड़ेपन की ओर ले जाएगा। भारत में आज रोज- रोज एक नए घोटाले का पता चल रहा है। अतिरिक्त व्यय हो रहा। सरकारी आय को ठीक से जमा नहीं किया जा रहा है। इन प्रसंगों में राजकोषीय घाटे पर अंकुश लगाना अत्यावश्यक है। अगर हम स्वयं आर्थिक अनुशासन अपनाना शुरू कर दें, घोटाले न्यूनतम रह जाएँ, कर अदायगी सुचारू रूप से हो तथा अनियमित व्यय रुक जाए तो राजकोषीय घाटा अपने आप कम हो जाएगा। इसके लिए विश्व मुद्रा कोष को कहना नहीं पड़ेगा।